

बोर्डों की देयताओं की पुनर्संरचना करना आवश्यक होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उत्तराधिकारी कंपनी पर विगत की देयताओं का भार न पड़े। केन्द्रीय सरकार विभिन्न स्रोतों से अस्थायी वित्तपोषण की व्यवस्था करने में भी पूर्ण परिवर्तन की स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने वाले राज्यों की सहायता करेगी तथा इसे वित्तीय व्यवहार्यता के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्व निर्धारित सुधार कार्यों और यथोचित शासन व्यवस्था बनाए जाने से जोड़ा जाएगा।

5.4.4 वितरण में निजी उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए वितरण व्यापार में क्षमता पैरामीटरों के पूर्वनिर्धारित सुधारों के साथ पर्याप्त लाभ व उपयुक्त अस्थायी मॉडल के संबंध में अनुकूल व्यापारिक माहौल आवश्यक होगा। यूटिलिटियों एवं उपभोक्ताओं के लिए जोखिम को कम करने, क्षमता में सुधार व प्रणालीगत हानियों में तत्काल कमी की दृष्टि से बहु-वर्षीय टैरिफ (एमवाइटी) के माध्यम से निष्पादन आधारित विनियमन ढांचा महत्वपूर्ण है। आर्थिक और उन्नत सेवा गुणवत्ता के माध्यम से इससे जनहित संभव होगा। विद्युत खरीद कीमतों व मुद्रास्फीति सूचकांकों के ज्ञात संकेतकों तक टैरिफ समायोजन को प्रतिबंधित करके उपभोक्ता टैरिफ का अनुमान और अधिक आसान होगा। पारेषण एवं वितरण हानियों में अपेक्षित कमी प्राप्त करने तथा उपभोक्ताओं के लिए सेवा गुणवत्ता सुधारने के लिए वितरण में निजी क्षेत्र भागेदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.4.5 विद्युत अधिनियम, 2003 प्रतिस्पर्धी विद्युत उत्पादक कंपनियों और क्षेत्रीय वितरण लाइसेंसधारियों के अतिरिक्त व्यापारिक लाइसेंसधारियों को उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की बिक्री करने में सक्षम बनाता है जबकि राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा वितरण में खुली पहुंच प्रदान कर दी जाए। जैसे कि अधिनियम में अपेक्षित है एसईआरसी जून, 2005 तक विनियमकों को अधिसूचित करेगा जिससे धारा 42 की उपधारा-2 के संबंध में वितरण नेटवर्कों में खुली पहुंच मिल सकेगी। इस धारा में निर्धारित किया गया है कि जो उपभोक्ता किसी भी समय एक मेगावाट से अधिक विद्युत की अपेक्षा करते हैं उन्हें 5 वर्षों से पहले खुली पहुंच की अनुमति दी जाएगी। अधिनियम की धारा 49 में प्रावधान है कि जिन उपभोक्ताओं को धारा 42 के अंतर्गत खुली पहुंच प्रदान की गई है वे टैरिफ समेत इस प्रकार की शर्तों व निबंधनों, जैसा कि उनके बीच सहमति हो, पर किसी भी व्यक्ति के साथ समझौता निष्पन्न कर सकते हैं। वितरण में खुली पहुंच हेतु विनियम बनाते समय एसईआरसी व्हीनिंग प्रभार और क्रॉस सब्सिडी प्रभार जैसा कि अधिनियम की धारा 42 में अपेक्षित है का भी निर्धारण करेगा।

5.4.6 राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा ऊर्जा लेखा सुनिश्चित करके तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों की अलग-अलग पहचान करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक विनिर्दिष्ट यूनिट में ऊर्जा गणना और इसके परिणामों की घोषणा, राज्य वि. वि. आयोगों के अनुसार, मार्च, 2007 तक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। शासन व्यवस्था और निवेश में उपयुक्त सुधारों के साथ हानियों में कमी करने का एक कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। इन हानियों को सन् 2012 तक अंतराष्ट्रीय मानकों तक नीचे लाया जा सके।

5.4.7 वितरण में प्रतिस्पर्धा के संबंध में अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में एक प्रावधान समान आपूर्ति क्षेत्र में अपने स्वतंत्र वितरण प्रणालियों के जरिए विविध लाइसेंसधारियों की अवधारणा के रूप में शामिल है। राज्य सरकारों को सरकारी यूटिलिटियों की पुनर्संरचना करते समय वितरण जोन बनाने की पूर्ण नम्यता प्राप्त है। किसी मौजूदा वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र के अंतर्गत दूसरा और

उत्तरवर्ती वितरण लाइसेंस प्रदान करने के लिए छोटे शहरी क्षेत्र हेतु एक नगरपालिका परिषद् एक राजस्व जिला और बड़े शहरी क्षेत्र हेतु एक नगरपालिका निगम को न्यूनतम क्षेत्र मान लिया जाए जैसा कि भारत के संविधान (74वें संशोधन) के अनुच्छेद 243 (थ) में परिभाषित है। भारत सरकार अधिनियम की धारा 14 में परिकल्पित किए गए दूसरे और उत्तरवर्ती वितरण लाइसेंस हेतु आवेदक द्वारा अनुपालन की जाने वाली आवश्यकताओं 3 माह के भीतर अधिसूचित करेगी। सभी उपभोक्ता वर्गों को प्रतिस्पर्द्ध का लाभ प्रदान करने की दृष्टि से दूसरा तथा उत्तरवर्ती वितरण लाइसेंस धारक विद्युत अधिनियम 2003 के खण्ड 43 के प्रावधानों के अनुसार उसी क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने का जिम्मेवार होगा। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वसूली किए जाने वाले कनैक्शन प्रभारों समेत टैरिफ का विनियमन एसईआरसी द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा। इसमें यह सुनिश्चित होगा कि दूसरा वितरण लाइसेंसधारक उपभोक्ताओं से गैर-युक्तिसंगत कनैक्शन प्रभार की मांग नहीं कर सकेगा।

5.4.8 अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर एक सही मीटर के जरिए विद्युत की आपूर्ति करने का शासनादेश है। प्राधिकरण द्वारा 3 माह के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 5.5 के अधीन अपेक्षित विनियम बनाए जाने चाहिए।

5.4.9 अधिनियम के अंतर्गत दो वर्षों के भीतर सभी उपभोक्ताओं की मीटरिंग किया जाना अपेक्षित है। एसईआरसी वितरण लाइसेंसधारियों से उनका मीटरिंग प्लान प्राप्त कर सकता है, उसे अनुमोदन प्रदान कर सकता है और उसे अधिसूचित कर सकता है। एसईआरसी को पूर्वदत्त मीटरों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। प्रथमतः न्यूनतम एक एमवीए भार वाले बड़े उपभोक्ताओं के लिए टीओडी मीटरों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एसईआरसी को खतंत्र तृतीय पार्टी मीटर परीक्षण व्यवस्था भी करनी चाहिए।

5.4.10 लागत और लाभ को ध्यान में रखते हुए यूटिलिटियों द्वारा प्राथमिकता आधार पर आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियां क्रियान्वित की जाए ताकि नेटवर्क सूचना तथा ग्राहक डाटा बेस तैयार किया जा सके जिससे भार प्रबंधन, गुणवत्ता सुधार, चोरी और हेराफेरी राकने, ग्राहक सूचना और सभी मीटरीकृत उपभोक्ताओं को सही-सही और शीघ्रतापूर्वक बिल जारी किए जा सकें और बसूली की जा सके। समयबद्ध तरीके से उपभोक्ता इंडेक्सिंग वे मैपिंग पर विशेष जोर प्रदान किया जाना चाहिए। त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों को सहायता पहले से ही प्रदान की जा रही है।

5.4.11 परेषण एवं वितरण (टी एण डी) हानियों (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) को कम करने चोरी रोकने, उन्त वोल्टेज प्रोफाइल तथा बेहतर उपभोक्ता सेवा के लिए एलटी/एचटी अनुपात घटाने हेतु उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

5.4.12 वितरण प्रणालियों के कुशल कार्यकरण के लिए एससीएडीए और आंकड़ा प्रबंधन प्रणालियां अनिवार्य पूर्व आवश्यकताएं हैं। एसईआरसी द्वारा वितरण लाइसेंसधारियों से एससीएडीए और आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम प्राप्त किया जाना चाहिए तथा उनका अनुमोदन किया जाना चाहिए। चरणबद्ध तरीके से सब-स्टेशन ऑटोमेशन इविपमेट के संस्थापन हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।

5.4.13 अधिनियम में बिजली चोरी के विरुद्ध कठोर उपायों का प्रावधान किया गया है। राज्यों और वितरण यूटिलिटियों को इन प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य सरकारें विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकते हैं, जैसी कि अधिनियम की धारा 153 में परिकल्पना की गई है।

5.5 सेवा लागत व लक्षित सब्सिडी की वसूली

5.5.1 विद्युत क्षेत्र को कायम रखने के लिए उपभोक्ताओं से सेवा लागत की वसूली सुनिश्चित करने की अत्यंत जरूरत है।

5.5.2 अत्यंत गरीब श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत को वहनीय बनाने के लिए एक न्यूनतम सहायता रत्तर की जरूरत है। सभी उपभोक्ताओं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और 30 यूनिट प्रतिमाह के विनिर्दिष्ट रत्तर से कम उपभोग करते हैं को टैरिफ में विशेष सहायता प्रदान की जा सकती है जो कि क्रॉस सब्सिडी के रूप में होगी। उपभोक्ताओं के ऐसे विनिर्दिष्ट समूह हेतु टैरिफ आपूर्ति की औसत (समग्र) लागत का कम-से-कम 50% होगी। पांच वर्षों के बाद इस प्रावधान की पुनः समीक्षा की जाएगी।

5.5.3 पिछले कई वर्षों से क्रॉस सब्सिडियां गैर-पोषकीय रत्तरों तक बढ़ी हैं। क्रॉस सब्सिडियां प्रचालन में अदक्षताओं और हानियों को छुपाती हैं। उपभोक्ताओं को बिना कोई टैरिफ हानि पहुंचाए इस असंतुलन को ठीक करने की नितांत आवश्यकता है उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों के लिए वर्तमान क्रॉस सब्सिडियों को प्रगतिशील रूप से और धीरे-धीरे कम करने की आवश्यकता होगी।

5.5.4 अधिनियम की धारा 65 की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार को इस सीमा तक सब्सिडी देना चाहिए जिससे आवश्यक बजट प्राबधान किया जा सके ताकि यूटिलिटी को वित्तीय समस्या का सामना न करना पड़े, जो उसके प्रचालन को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार के प्रयास किए जाएं जिसमें अत्यंत पारदर्शी और दक्षतापूर्ण तरीके से लक्षित किए गए लाभार्थियों तक सब्सिडी की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके।

5.6 प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान तथा विकास (आर एण्ड डी)

5.6.1 कुशल और किफायती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण के सभी उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी समुपयोजन का महत्व अधिक है। बृहत और संकीर्ण विद्युत प्रणालियों के प्रचालन एवं प्रबंधन के लिए सम्मिलित विविध एजेंसियों के मध्य समन्वय की आवश्यकता है। राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय रत्तर पर विद्युत प्रणाली का प्रभावी नियंत्रण केवल सूचना प्राद्योगिकी के उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है। आईटी के इस्तेमाल में वितरण संबंधी तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां कम रहने तथा उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त सेवाएं प्रदान करने की विशाल क्षमता विद्यमान है। एकीकृत संसाधन आयोजना और मांग पक्ष प्रबंधन के लिए नवीनतम विकसित प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना भी आवश्यक होगा।

अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों के संबंध में अनुसंधान, विकास, निर्दर्शन एवं वाणिज्यिककरण हेतु विशेष प्रयास किए जायेंगे। इस प्रकार की प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों, विनिर्देशों तथा निष्पादन मानदंडों का अनुपालन करना होगा।

5.6.2 विद्युत उत्पादन हेतु सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी और आईजीसीसी जैसी कुशल प्रौद्योगिकियों तथा बड़े आकार की यूनिटों को धीरे-धीरे इस्तेमाल में लाया जाएगा क्योंकि इनकी लागत किफायती है। साथ ही, उड़न राख के उत्पादककारी उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास और उनके प्रयोग को प्राथमिकता एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

5.6.3 इसी प्रकार न्यूनतम संभावित हानियों के साथ लंबी दूरी तक उच्च वोल्टता की विद्युत पारेषित करने के लिए किफायती प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होगी। मिश्रित उत्पादन एवं पारेषण प्रचालनों के लिए सुविज्ञ नियंत्रण प्रणालियों समेत विद्युत उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने, दक्ष वितरण व्यापार और उपभोक्ता के अनुकूल परिस्थितियों के लिए विशेष सूचना प्रौद्योगिकी विकसित करने की आवश्यकता है।

5.6.4 देश के विद्युत क्षेत्र में ठोस अनुसंधान एवं विकास आधार मौजूद है जिसे और आगे बढ़ाया जाएगा। अभिज्ञात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आर एण्ड डी कार्यों में तेजी लाई जाएगी और मिशन की स्थापना की जाएगी। विद्युत क्षेत्र में आर एण्ड डी को प्रोत्साहित करने के लिए एक उपयुक्त वित्त पोषण तंत्र तैयार किया जाएगा। बड़ी विद्युत कंपनियों को अपने लाभ में से कुछ भाग आर एण्ड डी के लिए रखना चाहिए।

5.7 उपभोक्ताओं के हितों के लिए लक्षित प्रतिस्पर्धा

5.7.1 बाजार के विकास को उन्नत करने के लिए नई उत्पादन क्षमताओं के एक हिस्से की दीर्घकालीन पीपीए से बाहर बिक्री की जाए। जैसे-जैसे विद्युत बाजार विकसित होंगे इससे लंबी अवधि की विद्युत खरीद करार फ्रेमवर्क के बाहर प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन लागत के साथ परियोजनाओं का वित्त पोषण संभव हो सकेगा। आगामी वर्षों में नए उत्पादन रेटेशनों की संस्थापित क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्द्धात्मक बातावरण बनाने में सहायक होगा। इससे

विद्युत बाजार की गहनता में वृद्धि होगी और उत्पादक और लाइसेंसी/उपभोक्ताओं दोनों के लिए और अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे और इससे दीर्घकाल में टैरिफ में कमी आएगी।

इसके लिए नीति में निम्नांकित बातों को ध्यान रख जाए:-

(क) अन्तरराज्यीय व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करना केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का कार्य है इससे सारे देश में व्यापार का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग राज्य के अंदर वाणिज्य हेतु लाइसेंस जारी करेंगे।

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा शुरू किए गए एबीटी व्यवस्था का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को राज्यीय स्तर पर एबीटी व्यवस्था शुरू करने का परामर्श दिया गया है। इससे अधिक्य वाले लाइसेंसों से कमी वाले लाइसेंसों तक इन्ट्रा-डे विद्युत स्थानांतरणों के लिए विश्वसनीय समाधान तंत्र भी सुगम बन पाया है।

(ग) कैप्टिव विद्युत उत्पादक संयंत्रों को अनुमति प्रदान की जानी चाहिए कि वे लाइसेंसधारियों और उपभोक्ताओं को विद्युत की बिक्री कर सके जब उन्हें अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत एसईआरसी द्वारा खुली पहुंच की अनुमति प्राप्त हो जाए।

(घ) उपयुक्त आयोग द्वारा विद्युत बाजार का विकास सभी संबंधितों के साथ परामर्श से किये जाने की आवश्यकता है।

(ङ.) केंद्रीय आयोग और राज्य आयोगों को क्रमशः अधिनियमों की धारा 170 और 181 के अंतर्गत अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। इन विनियमों से प्रतिरप्ति को प्रोत्त्वाहन प्रदान करने और उपयोग संरक्षण से संबंधित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। विनियामक आयोगों को विभिन्न विनियमों को शीघ्र ही अधिसूचित करने की सलाह प्रदान की जाती है।

(च) राज्य के भीतर और बाहर व्यापार संबंधी विनियम तथा विद्युत विनियम के लिए भी विनियमों को 6 माह के भीतर उपयुक्त आयोगों द्वारा अधिसूचित करा जाएगा।

5.8 निजी क्षेत्र भागीदारी सहित विद्युत क्षेत्र कार्यक्रमों को वित्त प्रदान करना

5.8.1 गृह विद्युतीकरण सहित 'सभी के लिए विद्युत' और त्वरित आर्थिक विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, यह अनुमान लगाया गया है कि उत्पादन, पारेषण, सब-पारेषण, वितरण और ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए वर्ष 2002-03 के मूल्य स्तर पर 9,00,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। विद्युत बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों स्तरों पर सार्वजनिक क्षेत्र निवेशों को बढ़ाना होगा। क्षेत्र के अपेक्षित विस्तार के महत्व पर विचार करते हुए, निवेशों के एक निश्चित भाग को निजी क्षेत्र से लाने की आवश्यकता भी होगी। यह अधिनियम विभिन्न घटकों में प्रवेश अवरोधों को हटाकर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता है। अधिनियम की धारा 63 विभिन्न घटकों में प्रतियोगी आधार पर आपूर्तिकर्ताओं की भागेदारी का प्रावधान करती है जिससे निजी क्षेत्र निवेश और अधिक बढ़ेगा। सार्वजनिक सेवा दायित्वों जैसे ग्रामीण घरों और छोटे एवं सीमातः कृषकों को विद्युत की पहुंच प्रदान किए जाने को सार्वजनिक वित्तपोषण के संबंध में प्राथमिकता मिलेगी।

5.8.2 सार्वजनिक क्षेत्र को आंतरिक संसाधन विकसित करने में समर्थ होना चाहिए जिससे कम-से-कम एक समयबद्ध तरीके से अपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र और राज्यों में सरकार से उचित सकल बजटीय सहायता के पश्चात् भी निवेशों की इक्विटी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इसके लिए यह जरूरी होगा कि निवेशों पर रिटर्न के माध्यम से अधिक उत्पादन किया जाए और इसके साथ-साथ डेप्रीसिएशन रिजर्व सृजित किया जाए ताकि ऋण सेवा ५८० G/०५-३

दायित्व से निपटा जा सके। इससे परियोजना सिर्फ वित्तीय समापन में ही समर्थ नहीं होगी बल्कि विस्तार कार्यक्रमों के लिए भी उसकी बैंक संबंधी क्षमता में भी सुधार होगा साथ ही केन्द्र व राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों और निजी क्षेत्र परियोजनाएं भी इन्क्रिटी वित्तपोषण व ऋण पुनःअदायगी संबंधी अपने दायित्वों को पूर्ति करने की स्थिति में आ सकेंगे।

5.8.3 अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के अंतर्गत खुली पहुंच के अंतर्गत वैकल्पिक आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं पर संबंधित राज्य आयोगों द्वारा अधिभार वसूल किया जाना है। इससे इस प्रकार के उपभोक्ताओं को टैरिफ के कारण क्रास सब्सिडी घटक से होने वाली हानि के लिए धारा 42 (2) के अंतर्गत खुली पहुंच की अनुमति वाले ऐसे उपभोक्ताओं के लिए कार्य कर रहे वितरण लाईसेंसी को प्रतिपूर्ति प्रदान की जा सकेगी। खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं के मामले में आपूर्ति के प्रति अपनी देयताओं से उत्पन्न होने वाले वितरण लाईसेंसी की स्थायी लागत को पूरा करने के लिए धारा 42 की उपधारा (4) के अंतर्गत एक अतिरिक्त अधिभार भी वसूल किया जा सकता है। खुली पहुंच की अनुमति वाले उपभोक्ताओं से वसूल किया जाने वाला अधिभार और अतिरिक्त अधिभार इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि अधिनियम की धारा 42 (2) के अंतर्गत खुली पहुंच के प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत की आपूर्ति करने और विद्युत उत्पादन करने में प्रत्याशित की गई प्रतिस्पर्द्ध समाप्त हो जायेगी। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक है कि अधिभार को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (2) में अनुमानित की गई क्रास सब्सिडी में कटौती के साथ ही चरणवार उत्तरोत्तर रूप में कम किया जाए।

5.8.4 पूँजी की कमी है। निजी क्षेत्र में निवेश के लिए विविध विकल्प मौजूद हैं। अतः निवेश पर प्रतिफल उस ढंग से प्रदान किए जाने की आवश्यकता है जिससे क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में निवेश अवसरों के समकक्ष, यदि वरीयता में न हों तो, पर्याप्त निवेश आकर्षित करने में सक्षम हो सके। स्पष्टः यह अवसरों और जोखिमों के मूल्यांकन और उन्हें स्पष्ट समझे जाने पर आधारित होगा। उपभोक्ताओं की अभिरुचि और निवेशों की आवश्यकता के बीच उपयुक्त संतुलन बनाना पड़ेगा।

5.8.5 उद्योग के सभी खण्डों में संचालनों की दक्षता को सुधारने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। प्रोत्ताहन और अप्रोत्ताहन के साथ प्रचालनों के उचित कार्यक्षमता मानकों को उपभोक्ताओं के साथ तैयार करके दक्ष प्रचालनों के लाभ में हिस्सेदारी के लिए उचित व्यवस्था विकसित किए जाने के साथ तैयार करने की आवश्यकता होगी। इससे एक तरफ तो उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी वहीं दूसरी तरफ प्रचालनों की दक्षता को सुधार हेतु प्रेरणा प्राप्त होगी।

5.8.6 उन मामलों में उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्द्ध के लाभ प्राप्त होंगे जहां प्रतिस्पर्द्ध प्रचालन मानकों और पैरामीटरों के आधार पर लागत के बजाय कीमत का निर्धारण करेंगे। उपभोक्ताओं के संपूर्ण हित में विद्युत उद्योग को शीघ्रातिशीघ्र इस स्थिति में लाने के लिए सभी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया हेतु विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत, जैसा कि अधिनियम की धारा 63 में निर्धारित है, जारी कर दिए गए हैं।

5.8.7 इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी उत्पादक कंपनियों, पारेषण लाईसेंसी तथा वितरण लाईसेंस धारकों को अपनी प्रचालनात्मक दायित्व निभाने के लिए उचित भुगतान प्राप्त हो ताकि वे विस्तृत नार्यक्रमों के लिए नए सिरे से जरूरी निवेश कर सकें। इसलिए क्षेत्र के विकास के लिए

प्रचालन कार्यों व व्यापार की वित्तीय व्यवहार्यता अनिवार्य होगी। क्षेत्र की वित्तीय स्थिति पुनः बहाल करने के लिए अथक प्रयास करने अपेक्षित होंगे। इस प्रयोजन से एसईआरसी द्वारा टैरिफ का यौक्तिकरण सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। इसमें मूल, अंतरीय व व्यस्ततमकालीन विद्युत हेतु विभिन्न प्रकार से कीमत निर्धारण किया जाना शामिल है।

5.8.8 विनियामक आयोगों की स्वतंत्रता और निवेशकों के मध्य विश्वास जगाने में उनकी कार्यप्रणाली की पारदर्शिता के आधार पर विनियामक निश्चितता की आवश्यकता का समाधान करने के लिए भी उपाय किए जाएंगे।

5.8.9 क्षेत्र की बढ़ती निवेश आवश्यकताओं के मद्देनज़र विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में निजी भागेदारी की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होगी। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को सरकारी तथा निजी भागेदारी के लिए कार्यक्षम तथा सफल मॉडल विकसित करने की जरूरत है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र वित्तपोषण के साथ-साथ निजी निवेश में भी वृद्धि की जा सकेगी। विद्युत क्षेत्र में निजी भागेदारी प्रोत्साहित करने के लिए प्रक्रियागत सरलीकरण के निमित्त उद्योग से निरंतर बातचीत करने का तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

पारेषण एवं वितरण हानियां

5.8.10 यह स्पष्ट है कि जब तक कि टी एंड डी हानियों को पर्याप्त रूप से और तीव्रता से कम न किया जाए विद्युत क्षेत्र व्यावहारिक नहीं रहेगा। हाल ही के वर्षों में बड़ी संख्या में राज्य 40% से अधिक हानियां दर्ज करते रहे हैं। किसी भी दृष्टि से ये अस्थिर हैं और इसमें विद्युत क्षेत्र प्रचालन का निरंतर गिरावट अंतर्निहित है। हानियों में वर्तमान रत्तर के जारी रहने से न केवल विद्युत क्षेत्र प्रचालन को चुनौती का सामना करना पड़ेगा बल्कि समग्र रूप से भावी आर्थिक विकास भी खतरे में पड़ जाएगा।

राज्य सरकारें एक पंचवर्षीय योजना तैयार करेगी जिसमें इन हानियों में तेजी से कमी लाने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे इन हानियों में कमी करने के लिए अभियान के प्रयासों में सामाजिक भागेदारी, प्रभावी प्रवर्तन, संस्थाओं के लिए प्रोत्साहन, स्टाफ और उपभोक्ताओं तथा प्रौद्योगिकीय उच्चीकरण को शामिल किया जाना चाहिए। केंद्रीय सरकार को उन राज्यों को प्रोत्साहन आधारित सहायता प्रदान करेगी जो कि सहमत कार्यक्रमों के अनुसार हानियां कम करने में सक्षम है।

5.9 ऊर्जा संरक्षण

5.9.1 ऊर्जा क्षमता और मांग पक्ष प्रबंधन उपायों द्वारा विद्युत की महत्वपूर्ण बचत की जा सकती है। समग्र जरूरतों को कम करने के लिए ऊर्जा संरक्षण और मांग की दिशा में प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है और ऊर्जा दक्षता व्यूरो गठित किया गया है।

5.9.2 संस्थापनाओं, जहां मांग पक्ष प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण उपाय संबंधी अनेक उपाय किए जाने हैं, की संभावित संख्या काफी अधिक है। इसके लिए ऊर्जा दक्षता व्यूरो (बीईई) द्वारा कार्य आरंभ

किया जाएगा। राष्ट्रीय विद्युत आयोजना प्रक्रिया हेतु विचार करने के लिए अनुमानित संरक्षण और संभावित डीएसएम लागत अनुभानों सहित उपलब्धि को बीईई द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

5.9.3 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विद्युत संघनता वाले उद्योगों के लिए आवधिक ऊर्जा लेखा परीक्षा को अनिवार्य बनाया गया है। ऊर्जा लेखा परीक्षाओं को अपनाने और ऊर्जा संरक्षण उपायों को बढ़ाने के लिए अन्य उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी सरकारी भवनों में ऊर्जा संरक्षण के लिए अनेक उपाय किए जाएंगे जिनसे लगभग 30% ऊर्जा की बचत होने की संभावना है। इस प्रयास में सौर, जल, तापन प्रणाली और सौर ऊर्जा निष्क्रिय आर्किटेक्चर महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

5.9.4 ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में आरंभिक पहल स्वैच्छिक और स्व-विनियामक होगी जिसके साथ उपकरणों पर लेबल लगाने पर बल दिया जाएगा। जैसे-जैसे जागरूकता बढ़ेगी एक विनियामक एप्रोच के लिए मानकों का गठन किया जाएगा।

5.9.5 कृषि के क्षेत्र में पम्पसेट लगाए जायेंगे और जल की उपलब्धता प्रणाली को अधिक कारगर बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा क्षमता प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र को दर्शाने हेतु ऊर्जा लेखा परीक्षा का कार्य किया जाएगा। कृषि व औद्योगिक क्षेत्र में मोटर तथा ड्राइव सिस्टम अधिक खपत के प्रमुख खोत हैं। औद्योगिक, वाणिज्यिक और घरेलू संस्थापनाओं में ऊर्जा दक्षता प्रकाश प्रौद्योगिकियां अपनाई जाएंगी।

5.9.6 क्षमता अभिवृद्धि की जरूरत को कम करने के लिए अधिकतम आवश्यकता अवधि (पीक परियड) के दौरान और ऑफ पीक पीरियड विद्युत क्षेत्र की मांग के अंतर को कम करना होगा। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त भार प्रबंधन तकनीक अपनाई जानी चाहिए। व्यरततम और गैर-व्यरततमकालीन आपूर्ति के लिए टैरिफ ढांचा और मीटर लगाने की व्यवस्था(दिन के समय मीटरिंग) भार प्रबंध लक्ष्यों के अनुकूल होनी चाहिए। विनियामक आयोगों द्वारा ऊर्जा दक्षता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5.9.7 ऊर्जा संरक्षण उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऊर्जा सेवा कंपनियों की भूमिका को बढ़ाया जाएगा। ऐसी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के उपाय भी किए जाएंगे।

5.9.8 ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान जरूरी होगा ताकि विद्युत का कुशल उपयोग हो सके।

5.9.9 एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है। विशेष कार्य योजना के संदर्भ में सभी प्रस्तावित उपायों पर प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

5.10 पर्यावरण संबंधी मामले

5.10.1 व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा पर्यावरण कार्य योजना (ईएपी) क्रियान्वयन के माध्यम से उपयुक्त अग्रिम कार्रवाई के जरिए पर्यावरणीय चिंताओं की ओर ध्यान दिया जाएगा।